Nai Dunia (Indore), 31st August 2013, Page-6

आईआईटी की नकल पर आया प्रदेश का टेक्निकल एजुकेशन विभाग

नकल कर लो पर 'अकल' भी लगाना

प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रोफेसर्स की कमी और गिरते शिक्षा स्तर को देखते हुए राज्य शासन ने सोमवार को वर्चुअल क्लासेस की शुरुआत की है। इसके तहत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऑडियो, वीडियो के माध्यम से एक सेंटर से सारी जगह लेक्चर देखे और सुने जा सकेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजों की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) को दी गई हैं। उधर उच्च शिक्षा विभाग भी कुछ इसी तरह के प्रयास में लगा है।

› डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (डीटीई) ने आईआईटीज के तर्ज पर की वर्चुअल क्लास की शुरुआत

› उच्च शिक्षा विभाग भी कर रहा है वर्चुअल क्लास की प्लानिंग

i SPECIAL

indore@inext.co.in

INDORE (30 Aug.): टेक्निकल, प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल कोर्सेस में क्वालिटी एजुकेशन का स्तर अच्छा करने के लिए सरकार ने कई तरह के प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। एडमिशन सीजन खत्म होते ही अब ऐसी प्लानिंग की जा रही है, जिससे कॉलेजों की कमियां दूर की जाएं। प्रदेश में सबसे बड़ी परेशानी प्रोफेसर्स की कमी है। कॉलेजों को चाहकर भी अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार आईआईटीज की तर्ज पर वर्चुअल क्लास रूम की शुरुआत कर रही है।

एक टीचर से भी चल जाएगा काम

डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और उच्च शिक्षा विभाग दोनों की प्लानिंग करीब-करीब समान है। दोनों चाहते हैं कि किसी एक सेंटर से भी कॉलेजों के क्लास रूम को कनेक्ट कर दिया जाए। इसके लिए भोपाल में एक सेंटर बनाया गया है, जहां इंजीनियरिंग विषयों के एक्सपर्ट ऑनलाइन लेक्चर देंगे और प्रदेशभर के स्टूडेंट्स इसे देख और सुन सकेंगे।

टू-वे कम्यूनिकेशन

ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में प्रोफेसर सिर्फ लेक्चर ही नहीं दे सकेंगे बल्कि स्टूडेंट्स से सवाल-जवाब भी कर सकेंगे। इसके लिए कॉलेजों में वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इंदौर में फिलहाल आईआईटी इंदौर और एसजीएसआईटीएस में हाई स्पीड इंटरनेट और सिस्टम्स लगे हैं। दोनों सेंटर देशभर के आईआईटीज की क्लास से जुड़े हुए हैं और जब चाहे लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। एक तरह से ये भी टू-वे कम्यूनिकेशन होगा, जिससे रियल लेक्चर का अहसास होगा।

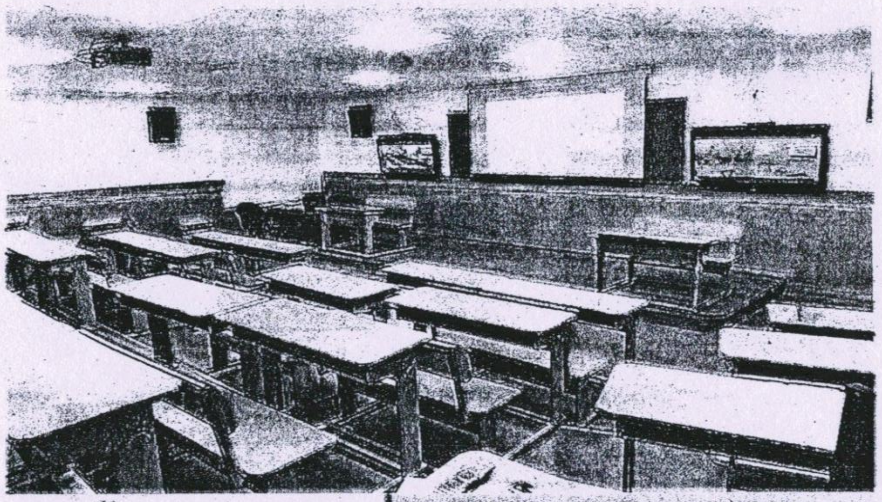

इसलिए पड़ी जरूरत

शहर में कई बड़ी आईटी कंपनियां आने वाली हैं। कुछ सालों में नए कैम्पस डेवलप होंगे और हजारों वैकेंसी निकलेंगी। इसके लिए जरूरी होगा कि प्रदेश के कॉलेज अभी से इसके लिए तैयार रहें। टीसीएस जैसी कंपनियां भी कह चुकी हैं कि प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। ऐसे में कॉलेज अपनी ओर से कोशिश करें ने करें, मगर सरकार ने इसके लिए वर्चुअल क्लास शुरू करके कोशिश शुरू कर दी है।

अलग से कंपनी को नहीं दिया काम

वर्चुअल क्लास की व्यवस्था संभालने के लिए देश के कुछ बड़े संस्थान प्राइवेट कंपनियों से समझौता करते रहे हैं। मगर प्रदेश में इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ही होगी। वैसे भी डीटीई के अधिकारियों के पास काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाने के बाद काफी समय फ्री होता है। ऐसे में इन्हें जिम्मेदारी देना सही कदम है। बचे हुए वक्त में ये इस काम को बखूबी कर सकेंगे।

आईआईटी इंदौर में कुछ इस तरह की वर्चुअल क्लास बनी हुई है। टेक्निकल एजुकेशन और उच्च शिक्षा विभाग भी इसी तर्ज पर प्लानिंग कर रहा है।

यहां होंगे सेंटर

डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मिली जानकारी के अनुसार वर्चुअल क्लास का मुख्यालय भोपाल में होगा। पूरे प्रदेश के कॉलेजों में वहीं से इंटरनेट के माध्यम से प्रसारण किया जाएगा। इंदौर के एसजीएसआईटीएस को दूसरा सेंटर बनाया जा सकता है। यहां से भी पूरे प्रदेश में ऑनलाइन लेक्चर का प्रसारण किया जा सकेगा। अन्य कॉलेजों को लेक्चर से कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस दिए जाएंगे।

यहां से आएंगे प्रोफेसर

ऑनलाइन लेक्चर प्रसारण के लिए आईआईटीज, एसजीएसआईटीएस और आरजीपीवी जैसे संस्थानों के प्रोफेसर्स की मदद ली जाएगी। कुछ प्राइवेट संस्थानों के अच्छे प्रोफेसर्स के लेक्चर्स भी ऑनलाइन किए जाएंगे। ऑनलाइन लेक्चर का एक डेटा बैंक भी तैयार किया जा रहा है, जिससे लेक्चर कभी भी देखे और सुने जा सकेंगे।

i CONNECT

अपना फीडबैक आप हमसे यहां शेयर कर सकते हैं.
facebook.com/indoreinext
mail us : indore@inext.co.in
Call or SMS: 9826022779

दो साल का टारगेट

सिस्टम की शुरुआत तो हो गई है लेकिन सभी कॉलेजों में एक साथ काम करने में समय लग सकता है। इसी बात पर डीटीई और उच्च शिक्षा विभाग भी सहमत है। उनका कहना है शहरों में तो वर्चुअल क्लास रूम आसानी से काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन गांवों में तकनीक को इंस्टॉल करने और समझाने में समय लग सकता है। अधिकारी यह मानकर चल रहे हैं कि इसके लिए दो साल का समय लग सकता है।

इन कॉलेजों का क्या होगा?

डीटीई से जुड़े इंजीनियरिंग कॉलेज तो किसी तरह ऑनलाइन उपकरणों और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी कॉलेजों की हालत काफी खराब है। यहां न अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन है और न ही उपकरण खरीदने के लिए बजट। ऐसे में सरकार को ही ऐसे कॉलेजों को फंड देना होगा।

एक डर तो ये भी है

लाइव लेक्चर में उपयोग होने वाले उपकरणों को संचालित करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। यानी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कम स्पीड वाले कनेक्शन से वीडियो देखना संभव नही होगा। परेशानी यह भी है कि जब बिजली ही गुल रहेगी या इंटरनेट कनेक्शन बंद रहेगा तक इस कंसेप्ट का क्या होगा?

" वर्चुअल क्लास रूम को शुरू करने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। बड़े अधिकारियों के बीच मीटिं में भी इस बारे में विस्तार से बात है। कुछ दिनों में ही फाइनल निर्ण हो जाएगा।

\- डॉ. नरेंद्र धाकड़,
एडिशनल डायरेक्टर, हायर एजुकेशन

" सोमवार से हमने ऑनलाइन लेक की शुरुआत कर दी है। अब सभी कॉलेजों को इनसे जोड़ा जा रहा इससे किसी कॉलेज में अगर प्रोफेसर नहीं होंगे तब भी पढ़ाई द नुकसान नहीं होगा।

\- डॉ. एल.एन. रेड्डी,
डिप्टी डायरेक्टर, डीटीई